basis. Government have also stated that for the successful conclusion of talks, creation of a positive environment by our interlocutors is a necessary ingredient.

Shelling by Pakistan Army

1758. SHRI KUSHOK THIKSEY: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the issue of incessant 'shelling by Pakistani Army in the Kargil District and the suffering of civilan population was discussed in the Indo-Pak talks (WAGAH MEET); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) and (b) Pakistani forces do engage in unprovoked firing across the Line of Control in Jammu & Kashmir, often targeting civilian areas and causing loss of life and damage to property. While Indian forces respond suitably, the issue of Pakistani firing on civilian areas has been taken up through established channels and also at the level of Prime Ministers. Government have demanded that this firing should cease.

Route to Kailash Manasarovar from Demchok

1759. SHRI KUSHOK THIKSEY:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister during his visit to Ladakh has promised in a public rally to approach the Chinese authorities to open the route to Kailash Manasarovar from Demchok in Leh district;

(b) if so, what has been the progress in the matter and details thereof; and

(c) whether Government are taking up the matter with the visiting Chinese delegates to India?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) Taking into account the growing popularity of the Kailash Mansarovar Yatra, the constraints relating to the existing route and requests from residents in the border areas, the Government have taken up proposals for an alternate/additional route for the Kailash Manasarovar Yatra with the Chinese Government. The route through Demochok (Ladakh, Jammu & Kashmir) is one of the alternative routes proposed to the Chinese side.

The Chinese side have pointed out that travel via Demochok would involve longer distances, in an environment having inadequate infrastructure and poor logistical facilities. They have also expressed the view that development of infrastructure in these remote areas would not be an easy task and building facilities for alternative routes could take a long time.

Government of India, for its part, are willing to consider new routes taking into account the availability of infrastructure and logistical facilities and other relevant factors. Our efforts to open a new route are continuing.

परमाणु संयम के संबंध में पाकिस्तान से साथ चर्चा

1760. **प्रो० रामगोपाल यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने परमाणु संयम के संबंध में भारत के साथ चर्चा का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय और स्थान निर्धारित करने की दिशा में कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो पाकिस्तान के उक्त प्रस्ताव पर सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) से (ग) संयुक्त वार्ता प्रक्रिया के भाग के रूप में भारत और पाकिस्तान विश्वासोत्पादक उपायों सहित शान्ति तथा सुरक्षा पर बातचीत कर रहे हैं। अक्तूबर, 1998 में इस विषय पर पहले दौर की बातचीत के दौरान विभिन्न प्रस्तावों का

आदान-प्रदान हुआ, जिसमें पाकिस्तान का नाभिकीय संयम से सम्बद्ध प्रस्ताव भी शामिल था। भारत ने हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं की ओर पाकिस्तान का ध्यान केन्द्रित किया जो वस्तुतः हमारे आकार, अवस्थिति और सम्पत्तियों की वजह से है न कि किसी देश विशेष की वजह से। हमने इस बात पर बल दिया है कि हमारी रक्षा स्थिति आक्रमण करने की नहीं है। इस संदर्भ में भारत ने मौजूदा विश्वासोत्पादक उपायों के उन्नयन तथा नाभिकीय और परम्परागत क्षेत्रों में नए विश्वासोत्पादक उपायों को रखने की आवश्यकता का प्रस्ताव किया। सरकार ने यह भी घोषणा की कि भारत विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाए रखेगा, पहले प्रयोग न करने के सिद्धान्त का अनुसरण करेगा, और आगे नाभिकीय परीक्षण विस्फोटों पर रोक लगाए रखेगा तथा हथियारों की दौड़ से अलग रहेगा। इसलिए भारत का दृष्टिकोण संयम तथा निग्रह की दृष्टि से अनुकरणीय है।

20-21 फरवरी, 1999 को प्रधान मंत्री की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान हमारे प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जिसमें इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश अनावश्यक अथवा नाभिकीय हथियारों के अनधिकृत उपयोग के खतरे को कम करने के संबंध में तत्काल उपाय करेंगे और नाभिकीय तथा परम्परागत क्षेत्रों में विश्वास पैदा करने के लिए उपायों का प्रतिपादन करने के उद्देश्य से संकल्पनाओं तथा सिद्धान्तों पर चर्चा करेंगे जिसका उद्देश्य युद्ध को रोकना है। इस अवसर पर भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक समझौता-ज्ञापन सम्पन्न हुआ, जिसके अन्तर्गत दोनों देश नाभिकीय तथा परम्परागत क्षेत्रों में जहां आवश्यक हो, विश्वास पैदा करने के लिए उपाय करेंगे और करार सम्पन्न करेंगे। इस समझौता-ज्ञापन में इस बात पर भी सहमति हुई कि बैठकों में दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी ब्यौरे तैयार किए जाएंगे, जो 1999 के मध्य में परस्पर सहमत तारीखों को होगी।

आई०एस०आई० के पास जाली भारतीय पासपोर्ट

1761. **श्री ईश दत्त यादव:**

प्रो० रामगोपाल यादव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई०एस०आई० के एजेन्टों ने बड़ी संख्या में भारतीय पासपोर्ट बनवा रखे हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने अब तक बनाए गये ऐसे कितने पासपोर्टों का पता लगाया है और उन एजेंटों ने यह पासपोर्ट किन-किन कार्यालयों और किस आधार पर बनवाये थे और इस कार्य के लिए कौन जिम्मेदार है; और

(ग) अब तक बनाए गये ऐसे सभी पासपोर्टों को रद्द करने के लिए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार कब तक और क्या त्वरित एवं ठोस कार्रवाई कर रही है?

विदेश मंत्रालय में (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) इस प्रकार की कोई खबर नहीं है। सरकार ऐसी सम्भावनाओं के प्रति सतर्क है तथा यथावश्यक कदम उठाने के लिए तैयार है।

Memorandum of understanding between India and Pakistan

1762. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign secretaries of India and Pakistan have, recently, signed a Memorandum of Understanding; and

(b) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir. During the recent visit of the Prime Minister to Pakistan, the Foreign Secretaries of India and Pakistan signed a Memorandum of Understanding on 21 February 1999.

(b) A copy of the MoU is attached here under.

Memorandum of understanding

The Foreign Secretaries of India and Pakistan:—

Reaffirming the continued commitment of their respective governments to the principles and purposes of the UN Charter;

Reiterating the determination of both countries to implementing the Simla Agreement in letter and spirit;

Guided by the agreement between their Prime Ministers of 23 September